



Neutral Citation No. - 2026:AHC:180456

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 30446 / 2026

दीपक उर्फ दाउदयाल

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता:

अंजली सिन्हा, राजेश कुमार दुबे,

सत्य प्रकाश पांडे

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार दुबे और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री भूपेंद्र पाल सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह जमानत याचिका मुकदमा अपराध संख्या 257/2025, धारा 80(2) व 85 भारतीय न्याय संहिता तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, थाना- बलदेव, जिला मथुरा के अंतर्गत विचारण के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने का अनुरोध करते हुए प्रस्तुत किया गया है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी मृतक का देवर है, जिसने 31.08.2025 को घरेलू मामलों पर मामूली विवाद के बाद शौचालय सफाई तेज़ाब पीकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद मृतक को उसके पति द्वारा अस्पताल ले जाया गया, हालांकि अपीलार्थी की पत्नी करिश्मा ने गलत बयान दिया है कि मृतक को उसके भाई द्वारा अस्पताल लाया गया था। आगे यह भी बताया गया है कि मृतक की मृत्यु घटना के चार दिन बाद हुई। यह भी बताया गया है कि उपचार के दौरान कोई मृत्यु पूर्व बयान दर्ज नहीं किया गया। अंत में यह बताया गया है कि पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



31.10.2025 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी (ससुर) की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765** मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त अपीलार्थी- **दीपक उर्फ दाउदयाल** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- i. अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. अपीलार्थी बिना किसी स्थगन का अनुरोध किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
- iii. अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।
- iv. अपीलार्थी अपने द्वारा निष्पादित मुचलके की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. मुचलके स्वीकार करने से पहले अपीलार्थी और जमानतियों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किए जाएंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. अपीलार्थी और जमानतदारों के मोबाइल संख्या और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से इस आदेश की डाउनलोड की गई प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसका सत्यापन संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

11. यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय अपीलार्थी की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति अपीलार्थी को **मथुरा जेल अधीक्षक** के माध्यम से ई-मेल या ई-कारागार पोर्टल के द्वारा और विचारण न्यायालय को ई-मोड के माध्यम से 24 घंटे के भीतर भेजे, जो **सर्वोच्च न्यायालय के जमानत मंजूरी की नीतिगत रणनीति** मामले में दिए गए आदेशों के अनुपालन में हो, जिसमें **स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 निर्णित 31.01.2023** को लिया गया था और **(2024) 10 एससीसी 685** में प्रकाशित हुआ था, साथ ही पीला पहन @ पीला पहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य के मामले में, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025 का निर्णय **29.05.2026** को लिया गया था।

13. यदि कोई आवेदन हो, तो उसका निस्तारण कर दिया गया है।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

31 अगस्त, 2026

ए.के.आर.